The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 7 | July 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

समावेशी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: एक समीक्षा

पूजा पांडे
रिसर्च स्कॉलर, मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की उत्तराखंड
गंगा सिंह
सहायक प्राध्यापक, शिक्षक-शिक्षा विभाग उत्तराखंड

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Keywords:
शिक्षा नीति, समावेशी शिक्षा, शिक्षा, प्रस्तावित, समावेशीकरण, सार्वभौमिक समाज

ABSTRACT

शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। शिक्षा पर सभी का अधिकार है अतः शिक्षा का अब समावेशीकरण हो रहा है जिसमें सबको समाहित कर ले, ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो अर्थात हर वर्ग के सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में एक विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। समावेशन सबके लिए सामान्य स्कूल के प्रत्यय को स्पष्ट करती है। यह एक ऐसा शैक्षिक प्रतिरूप है, जो सार्वभौमिक समाज के निर्माण एवं विकास के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को समान जगह देता है। यूनेस्को ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन, जेनेवा (2008) में समावेशी शिक्षा पर चर्चा की और स्पष्ट किया कि समावेशी शिक्षा छात्रों के गुणात्मक शिक्षा के मौलिक अधिकार पर आधारित है जो आधारभूत शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को समृद्ध बनाती है। समावेशी शिक्षा समाज के हर वर्ग के प्रतिभाशाली कमजोर औसत, मानसिक रूप

से कमजोर बालकों के लिए है जिससे वे समाज धारा में जुड़ते है आत्मविश्वासी होती है। इसका उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत की नई शिक्षा नीति इन्हीं लक्ष्यों को लेकर प्रस्तावित की गई है।

प्रस्तावना (Introduction)-

समावेशी शिक्षा वह क्षेत्र है जिसमें किसी भी नीति के सुझाव या सिफ़ारिश में चुनौतियों की संख्या के कारण अधिकतम कार्यान्वयन शेष रहता है। चूंकि समावेशी शिक्षा ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, अलग शिक्षा से लेकर समावेशी शिक्षा तक। पृथक शिक्षा से एकीकृत शिक्षा और एकीकृत से समावेशी शिक्षा की ओर यह यात्रा बहुत प्रभावशाली और सार्थक है। पहले विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, फिर समय-समय पर इसमें सुधार होता गया, जिससे यह समूह बुनियादी पूर्ति से संतुष्ट हो गया और समय के साथ मुख्यधारा में शामिल हो गया; बच्चों के हर समूह को करीब लाता है। एक ही छत के नीचे दोनों समूहों के साथ समान व्यवहार किया जाता है लेकिन अलग-अलग परिस्थितियों में। आख़िरकार देश की आज़ादी के बाद; कई नीतियों और आयोगों ने एकीकृत या विशेष शिक्षा के बजाय क्षेत्र में समावेशी शिक्षा के बारे में सुझाव दिया। आवश्यक लोग निश्चित रूप से अपनी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा से संतुष्ट हैं लेकिन एक ही छत के नीचे सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है जिसका लोगों को पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1968 में क्षेत्रीय असंतुलन, सामान्य स्कूल प्रणाली, लड़कियों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और मुख्यधारा की शिक्षा में सभी बच्चों के लिए सुविधाओं के संबंध में शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में सुझाव दिया गया है।यहां तक कि इस तरह की सिफारिशें आगे के शैक्षिक नीति दस्तावेजों जैसे एनपीई-1986, पीओए-1992, एनसीएफ-2005 और एनईपी-2020 में भी दी गई हैं। लेकिन आवश्यकताओं को उचित ठहराने के दृष्टिकोण की व्यावहारिकता के कारण कार्यान्वयन में बड़ी कमी है। कहीं न कहीं सीडब्ल्यूएसएन, विकलांग व्यक्तियों, अल्पसंख्यक समूहों, महिलाओं और अन्य सभी लोगों सहित सभी की स्वीकार्यता में समावेशी शिक्षा के हमारे उद्देश्य की कमी है। समावेशी शिक्षा के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ खड़ी हुई हैं और उन सभी चुनौतियों को पूरा करने के लिए एनईपी-2020 इसे बढ़ाने के उपाय ला रहा है। एक नज़र में शिक्षार्थियों के लिए

उपलब्धता और अनुकूल वातावरण बनाने में हितधारकों, शिक्षकों और अभिभावकों के सामने आने वाली चुनौतियाँ हैं। यहाँ तक कि शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी शिक्षकों को इस प्रकार के विशेष कौशल नहीं सिखाये जाते; इसलिए, शिक्षक किसी बिंदु पर कक्षा में बच्चे को संभालने में विफल हो जाएंगे। कहीं न कहीं, संस्थानों में बुनियादी ढांचे की कमी और प्रशासन में आर्थिक कमी विशेष बच्चों के लिए अवसरों और भागीदारी की हानि का कारण बनती है। एनईपी-2020 में समावेशी कक्षाओं और समावेशी समाज के संबंध में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समस्याओं के समाधान के बारे में सुझाव दिया गया है। एनईपी-2020 में दिए गए उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा, जिससे शिक्षा प्रणाली में अधिकतम समाधान प्राप्त किया जा सकेगा

शोध पत्र के उद्देश्य (Objectives of Research Paper)-

1.NEP 2020 में समावेशी शिक्षा के प्रावधानों का अध्ययन करना।

2. समावेशी शिक्षा के लिए निर्धारित योग्यता का अध्ययन करना।

3. समावेशी शिक्षा के द्वारा शिक्षा में आने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना।

4. समावेशी शिक्षा और NEP 2020 के अंतःसंबंधों का अध्ययन करना।

शोध विधि (Research Method)

यह शोध पेपर द्वितीयक श्रोतों पर निर्धारित है जिसके अंतर्गत अनेक समाचार पत्रों, शोध पत्रों, विभिन्न किताबों तथा विभिन्न वेबसाइटों की मदद ली गई है।

एनईपी 2020 में समावेशी शिक्षा (Inclusive Education in NEP- 2020)

कस्तूरीरंगन समिति (2019) द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। यह एक बहुत व्यापक नीति है। इसका कार्य शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करना है । एनईपी 2020 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुरूप है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को “शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांग और बिना विकलांग छात्र एक साथ सीखते हैं और शिक्षण और सीखने की प्रणाली को विभिन्न प्रकार के छात्रों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है । आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम ने 18 वर्ष की आयु तक विकलांग बच्चे के लिए

पर्याप्त स्थिति में मुफ्त शिक्षा के प्रावधान की भी पुष्टि की । आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम ने उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारी संस्थानों में बेंचमार्क विकलांग लोगों के लिए 3% आरक्षण को बढ़ाकर 5% कर दिया है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में सूचीबद्ध 21 विकलांगताओं में से कम से कम 40% विकलांगता वाले किसी भी व्यक्ति को विकलांगता वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अधिनियम में गैर-भेदभाव उपाय के रूप में बाधा मुक्त पहुंच पर भी जोर दिया गया ।

(क) स्कूली शिक्षा एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा के संबंध में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 द्वारा दी गई सभी सिफारिशों की पुष्टि करती है। नीति में विकलांग बच्चों के लिए बुनियादी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया को सक्षम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मध्यम से गंभीर विकलांगता वाले बच्चों के पास नियमित या विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होगा (एनईपी 2020, भाग- I, खंड 6.10)।

(ख) स्कूल परिसर को परिसर के अंदर ही एक संसाधन केंद्र और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। स्कूल को क्रॉस-विकलांगता प्रशिक्षण वाले विशेष शिक्षकों की भर्ती भी सुनिश्चित करनी होगी । विकलांग बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने और बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्कूल को व्यक्तिगत आवास और सहायता तंत्र प्रदान करने में सहायता की जाएगी (एनईपी 2020, भाग- I, धारा 6.11)।

ग) पाठ्यक्रम, सहायक उपकरण और सहायक उपकरण एनसीईआरटी के साथ काम करेंगे । डीईपीडब्ल्यूडी जैसे विशेषज्ञ निकाय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा बनाएंगे (एनईपी 2020, भाग- I, धारा 6.10) NIOS भारतीय सांकेतिक भाषा सिखाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित करने और इसके माध्यम से अन्य बुनियादी विषयों को पढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। पाठ्यक्रम बच्चों की ताकत के अनुसार लचीला होगा, जिससे बच्चे अपनी गति से काम कर सकेंगे। कक्षा की गतिविधियों में बच्चे को एकीकृत और संलग्न करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरण और अन्य सहायक उपकरण, साथ ही शिक्षण-सीखने की सामग्री की आवश्यकता होगी । जो पर्याप्त और भाषा-उपयुक्त हों जैसे बड़े प्रिंट वाली पाठ्यपुस्तकें और ब्रेल स्कूल में उपलब्ध कराए जाएंगे (एनईपी 2020, भाग- I, खंड 6.11)।

घ) शिक्षक एनईपी 2020 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार के बारे में बात करता है। विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए संवेदीकरण, शीघ्र हस्तक्षेप, समर्थन और विशेष शिक्षाशास्त्र, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग होना (एनईपी 2020, भाग- I, खंड 6.14)

च) मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, दिशानिर्देश तैयार करेगा और सिफारिश करेगा के लिए उपकरण विकलांग बच्चे का मूल्यांकन यह मूलभूत चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रवेश परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं के लिए होगा।

छ) होम स्कूलिंग गंभीर और गहन विकलांगता वाले बच्चों के लिए होम-स्कूलिंग विकल्प पहले की तरह उपलब्ध होगा। संसाधन केंद्र और विशेष शिक्षक होम-स्कूलिंग के लिए सहायता प्रदान करेंगे। होम-स्कूलिंग के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 में अनुशंसित सभी दिशानिर्देश और मानक विकसित किए जाएंगे । माता-पिता को अपने बच्चे की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान के माध्यम से माता-पिता का उन्मुखीकरण किया जाएगा (एनईपी 2020, भाग- I, खंड 6.12)

नई शिक्षा नीति एक व्यापक योजना है। इसमें वे सभी पहलू शामिल हैं जो शिक्षा प्रणाली में विकलांग बच्चों को पूर्ण रूप से शामिल करने में मदद करेंगे। निम्नलिखित पांच पहलू एनईपी 2020 में शामिल सभी बिंदुओं को एक संरचना देने का प्रयास है । सकारात्मक दृष्टिकोण दृष्टिकोण समावेशन में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। शिक्षा प्रणाली के एक स्तंभ के रूप में शिक्षक छात्रों में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ला सकता है। इसके लिए शिक्षकों को न केवल समावेशन के प्रति संवेदनशील होना चाहिए बल्कि समावेशन के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित भी होना चाहिए। एनईपी 2020 समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक मूल्यों और कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में सुधारों की बात करता है। स्कूल की तैयारी समावेशी शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब स्कूल विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हो। एनईपी 2020 स्कूल की तैयारियों को प्राथमिकता देता है। प्रत्येक स्कूल परिसर में संसाधन केंद्र और विशेष शिक्षकों की भर्ती और व्यक्तिगत सहायता कार्यक्रम समावेशन की दिशा में स्कूल की तैयारी के पहलू हैं। संसाधन एवं सहयोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक, सहायक उपकरण एवं अन्य संसाधन विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। जब एनईपी 2020 का समर्थन करने की बात आती है तो इसकी एक बहुत विस्तृत योजना है। संसाधन केंद्र न केवल स्कूल को बल्कि घर पर स्कूली शिक्षा देने वाले अभिभावकों को भी सहायता प्रदान करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल और अभिभावकों को राज्य द्वारा

सहायता प्रदान की जानी चाहिए। होम-स्कूलिंग प्रदान करने वाले माता-पिता के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी एनईपी 2020 का एक हिस्सा हैं । व्यक्तिगत कार्यक्रम कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसी तरह कोई भी दो विकलांग बच्चे एक जैसे नहीं होते। इसलिए, विभिन्न विकलांगताओं वाले प्रत्येक विकलांग बच्चे की अलग-अलग ज़रूरतें होती हैं। जब इन बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम डिजाइन करने की बात आती है तो कोई भी एक आकार सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता, यही सफलता की कुंजी है। एनईपी 2020 में स्कूल को इन बच्चों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम प्रदान करने का प्रावधान है। लचीला पाठ्यक्रम इन बच्चों की आवश्यकता और क्षमता उनके साथियों से बहुत अलग होती है और यही कारण है कि हम उन्हें वह नहीं सिखा सकते जो उनके साथी सीख रहे हैं। और इसीलिए इन बच्चों की बेहतरी के लिए एक लचीला पाठ्यक्रम और एक लचीला मूल्यांकन तंत्र बहुत आवश्यक है। एनईपी 2020 न केवल लचीले पाठ्यक्रम के बारे में बात करता है बल्कि आसान मूल्यांकन के लिए परख के बारे में भी बात करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

केवल विकलांग बच्चे की नियुक्ति से मदद नहीं मिलेगी। यदि हम एक देश के रूप में विकसित होना चाहते हैं, तो यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम हर बच्चे की विकलांगता की परवाह किए बिना शिक्षा को सुलभ बनाएं। विविधताओं का देश होने के नाते भारत हमेशा इन विविधताओं को एक अवसर के रूप में देखता है, उसी तरह अब समय आ गया है कि लोगों की मानसिकता बदले और हर विकलांगता को एक विशेष क्षमता के रूप में देखें। यानी केवल उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो वे नहीं कर सकते, उन पर ध्यान केंद्रित करना है कि ये बच्चे क्या बेहतर कर सकते हैं। पृथक्करण से समावेशन तक, भारत में समावेशी शिक्षा प्रणाली कई बाधाओं से गुजरती है। विकलांगता को एक विशेष योग्यता के रूप में देखने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। आख़िरकार, भारत सरकार एक ऐसी नीति लेकर आई जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण भी शामिल है। नई शिक्षा नीति 2020 को यदि उचित योजना के साथ लागू किया जाए तो यह समावेशी शिक्षा के लिए उत्प्रेरक साबित होगी। इससे समावेशी शिक्षा में आमूल-चूल बदलाव आएगा। ऊपर चर्चा किए गए सभी पहलू कुल मिलाकर विकलांग बच्चों के लिए प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जन्म देंगे। इससे समावेशी शिक्षा की अपेक्षा और वास्तविकता के बीच अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- नई शिक्षा नीति 14 व 6 अनुच्छेद ,की रूपरेखा 2020
- मिश्रा ,मृत्युन्जयजयपुर। ,एक समावेशी विद्यालय का निर्माण अरिहंत शिक्षा प्रकाषन ,
- Pandey, S.P. & Mansoori, Imtiyaj (2019), Creating an inclusive school, R. Lal Book Depot Meerut.
- www.education.gov.in> NEP 2020 MHRD.